मुख्यमंत्री खट्टर ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का नया जुमला फेंका

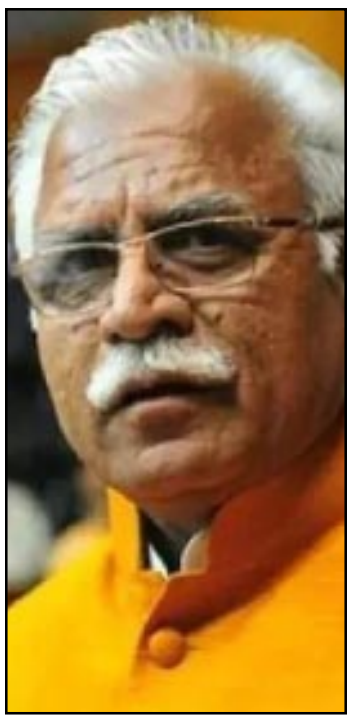

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) । सरकारी खजाना खाली होने के कारण कई विकास प्रोजेक्ट्स को धन देने से मना करने वाले झूठे घोषणावीर मुख्यमंत्री खट्टर ने जल्द ही वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा कर तीन हजार रुपये करने का जुमला फेका है। बेहतर होता कि सीएम बुजुर्गों के खाते में उनकी पेंशन हर बार समय पर पहुंचाने की घोषणा करते, सरकार बीते तीन माह से बुजुर्गों की पेंशन राशि नहीं दे पाई है।

खट्टर बीते मंगलवार को हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से रूबरू थे। विपक्षी पार्टियों की सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों को मुफ्त की रेवड़ी बताने वाली भाजपा के सीएम बुजुर्गों की रेवड़ियों में इजाफा करने की घोषणा कर गए, उन्होंने गर्व से यह भी दावा किया कि देश में सिर्फ हरियाणा ही सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन देता है। बताते चलें कि प्रदेश में बीते तीन माह से बुजुर्गों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। बुजुर्गों से समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी बताते हैं कि सरकार से अभी पैसा नहीं मिला है। जब सरकार धनराशि जारी करेगी तो खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

खट्टर ने ये नहीं बताया कि उनकी परिवार पहचान पत्र स्कीम के कारण प्रदेश में कितने हजार बुजुर्ग पेंशन से वंचित कर दिए गए। हरियाणा में पैदा हुए, यहीं काम किया और जब बुजुर्गी आई तो खट्टर के परिवार पहचान पत्र के कारण पेंशन से वंचित हो गए। खट्टर सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने परिवार पहचान पत्र की कमियां दूर कराने के बजाय इन बुजुर्गों की पेंशन ही खत्म कर दी। चलो मान भी लिया जाए कि उनका पहचान पत्र दुरुस्त नहीं है लेकिन उनकी उम्र और वृद्धावस्था तो सबके सामने है। इन बुजुर्गों को पेंशन कौन देगा? कुछ बुजुर्गो के मुताबिक अव्वल तो सरकार समय पर पेंशन खाते में डलवाती नहीं, यदि खाते की पेंशनराशि दो महीने में नहीं निकाली गई तो अगले महीने पेंशन ही बंद कर दी जाती है, सरकार बुजुर्गों को भी नहीं बख्श रही है।

चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, पहले लोकसभा चुनाव हैं फिर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। ऐसे में खट्टर खजाना खाली होने के बावजूद घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने केवल बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाने का जुमला ही नहीं फेका, घरों के ऊपर से गुजरने वाले बिलजी के तारों को हटवाने का लुभावना नारा उछाला। यही नहीं पूरे प्रदेश में घरों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों को शिफ्ट करने के लिए 151 करोड़ के खर्च की भी घोषणा कर डाली। यह घोषणा सिर्फ जुमला ही साबित होगी क्योंकि हाईटेंशन लाइन के टावर शिफ्ट करने में कई हजार करोड़ रुपयों का खर्च तो होगा ही टावरों के लिए जमीन का अधिग्रहण में होने वाला खर्च अलग होगा, इसके अलावा शिफ्टिंग के दौरान शटडाउन से अर्थव्यवस्था की जो हालत खराब होगी वो अलग, इसलिए समझ लीजिए न तो कोई शिफ्टिंग होनी है और न कोई खर्चा होना है, जुमले बाजों का यह चुनावी जुमला है।

राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम

एमसीएफ के बाद अब लूट की बारी एफएमडीए की

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) । अच्छे भले राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के जीर्णोद्धार की आड़ में बीते चार साल से लूट का खेल खेला जा रहा है और जब तक इन जुमलेबाजों की सरकार रहेगी ये खेल यूं ही चलता रहेगा। लूट की असल मलाई खाने के लिए मोदी-अमित शाह ने गुजरात से अपने प्यादे भेजे थे। शुरू में 115 करोड़ का एस्टीमेट बनाया गया, इससे पेट नहीं भरा तो लागत 127 करोड़ कर दी गई। फिर अधूरे स्टेडियम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 99 करोड़ का एस्टीमेट बनाया गया। गुजरातियों द्वारा असल मलाई खाने के बाद जूठी पत्तल एमसीएफ चाटती थी बाकी बची पत्तल चाटने का अधिकार एफएमडीए को दिया जा रहा है। विदित है कि एफएमडीए में भी वही चोर बैठे हैं जो पहले कभी नगर निगम फरीदाबाद में तो कभी नगर निगम गुड़गांव में थे।

करीब ग्यारह अंतरराष्ट्रीय और रणजी ट्रॉफी मैचों की रणस्थली रहे राजा नाहर सिंह स्टेडियम का जीर्णोद्धार करने के लिए निगम ने 2019 में 115 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया था। संघ-भाजपा की गुजराती

संजय भाटिया, पूर्व रणजी क्रिकेटर

लॉबी के दबाव में और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए खट्टर सरकार ने प्रोजेक्ट का ठेका गुजरात अहमदाबाद की रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड नाम की कंपनी को दे दिया। पूर्व रणजी खिलाड़ी संजय भाटिया ने आरोप लगाया था कि सरकार ने जिस रंजीत बिल्डकॉन को स्टेडियम का प्रोजेक्ट दिया वह सौ करोड़ रुपये काम करने के योग्य ही नहीं है, साथ ही उसे स्टेडियम बनाने का कोई अनुभव नहीं है।

संजय भाटिया का आरोप सही साबित हुआ, अनुभवहीन कंपनी ने काम तो तेजी से शुरू किया लेकिन तकनीकी पहलू सामने आने पर काम रुकने लगा। हालांकि निगम के खाऊ-कमाऊ अधिकारी कंपनी को भुगतान में देर नहीं करते। करीब 72 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी स्टेडियम तैयार नहीं हो सका। देरी होने से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने का जुमला उछाल कर रिवाइज्ड एस्टीमेट 127 करोड़ रुपये कर दिया गया।

प्रोजेक्ट में कमाई के रास्ते तलाशने वाले निगम अधिकारियों ने बचे हुए काम को पूरा कराने के लिए एक बार फिर 99 करोड़ रुपये का अतिरिक्त एस्टीमेट बना कर सरकार के पास भेज दिया। होना तो ये था कि प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने के लिए सरकार रंजीत बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जुर्माना लगाती और ब्लैक लिस्ट करती लेकिन खट्टर ऐसा करके आका मोदी को नाराज नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रोजेक्ट में हुई देरी और नुकसान की भरपाई कंपनी से न करके जनता से करने की योजना बना डाली। अब अधूरे स्टेडियम का प्रोजेक्ट एफएमडीए पूरा करेगा।

एफएमडीए अब इस अधूरे निर्माण के लिए नए सिरे से डीपीआर तैयार करेगा। बताते चलें कि स्टेडियम के अधूरे पड़े काम के लिए निगम ने 99 करोड़ का एस्टीमेट बनाया है, अंदेशा है कि एफएमडीए की नई डीपीआर इससे कहीं अधिक की होगी क्योंकि उन्हें भी तो इसमें नए सिरे से अपना हिस्सा चाहिए होगा।

मुख्यमंत्री खट्टर ने निगम के अधूरे पड़े कामों को एफएमडीए से पूरा कराने का ठेका ले रखा है मानो एफएमडीए के लोग जादू की छड़ी लेकर कहीं आसमान से उतरे हैं, ये भी उन्हीं के भाई बंधु हैं। यानी भ्रष्टाचार के इए नए पैटर्न में पहले नगर निगम किसी प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपये का एस्टीमेट बनाए और फिर उसे अधूरा छोड़ दे। सेक्टर 12 में नगर निगम की निर्माणाधीन इमारत इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री कार्रवाई करने के बजाय बकाया काम और नया एस्टीमेट बनाने का काम एफएमडीए पर छोड़ देंगे। इस तरह एक ही काम के लिए लगभग दो गुनी रकम चुकाई जा रही है।

सुधार या बिगाड़ : घरेलू हिंसा करने वाले पति बदमाशों की सूची में होंगे शामिल

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। दुष्कर्म, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न जैसे अपराध करने वालों पर पुलिस भले ही अंकुश नहीं लगा सके लेकिन पत्नी से मारपीट करने वाले पुरुषों को बदमाशों की सूची में शामिल कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के आदेश पर अब प्रदेश भर की पुलिस पत्नी आदी से मारपीट करने वाले पुरुषों की सूची बनाकर उन्हें बदमाशों की श्रेणी में शामिल करेगी।

डीजीपी शत्रुजीत कपूर बीते पांच अक्तूबर को नल्हर (नूंह) पहुंचे थे। नल्हर मेडिकल कॉलेज के सभागार में नूंह और पलवल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने घरों में महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले परुषों की सूची बनाने के निर्देश दिए। पुलिस ऐसे पुरुषों के साथ कड़ाई से पेश आएगी। हालांकि उन्होंने महिला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गश्त बढ़ाने, गांव तथा शहरी क्षेत्रों में शोहदों, महिलाओं से छेड़खानी करने वालों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए लेकिन दंपति के संबंध में सुनाया गया उनका आदेश चर्चा का विषय बना रहा।

पारिवारिक मामलों के जानकारों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई मामला शांत कराने के बजाय दंपति के बीच विवाद की खाई बढ़ाने का काम करेगी। जीवनभर साथ रहने वाले इस रिश्ते में पति को बदमाश के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से उसे जो मानसिक ठेस पहुंचेगी उससे दंपति के रिश्ते में और खटास आ सकती है। पति-पत्नी में अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इन्हें घरेलू हिंसा नहीं माना जा सकता। बहुत ही कम मामले होते हैं जिनमें शारीरिक हिंसा होती है। अधिकतर मामलों में चंद घंटों में समझौता भी हो जाता है।

पुलिस पर वैसे भी हत्या, चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसे गंभीर मामलों की तफ्तीश का बोझ है। तफ्तीश के बाद चार्जशीट, गवाह तैयार करना, सुबूतों का संकलन, अदालतों में हाजिरी जैसे रूटीन के काम के साथ अन्य नए केस की जांच करना, ऐसे में पत्नी से मारपीट करने वालों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग ही साबित होगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।